



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 32 राँची, बुधवार
15 श्रावण 1936 (श०)
6 अगस्त, 2014 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 241-251
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

1 अगस्त, 2014

संख्या-3/नि0सं0-09-107/2014 का. 7672-झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री राजकुमार, परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी को दिनांक 26 अप्रैल, 2014 से 20 मई, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

1 अगस्त, 2014

संख्या-3/से0वि0-04-26/2014 का. 7684-झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री चन्द्र किशोर मण्डल, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद को दिनांक 22 नवम्बर, 2000 से 28 फरवरी, 2001 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

1 अगस्त, 2014

संख्या-3/नि0सं0-09-91/2014 का. 7685--श्रीमती स्कोलास्तिका किरो, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 को (का) दिनांक 5 जनवरी, 2005 से 9 जनवरी, 2005 तक एवं (ख) दिनांक 24 जनवरी, 2005 को उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व एवं सुधार विभाग

अधिसूचना

2 अगस्त, 2014

संख्या-2/रा0. स्था0-36/14-3101/रा.-- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to Fair Compensation and Transparency in Law Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act.-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ पदनाम से प्रदत्त की जाती हैं : -

क्र. सं.	पदनाम
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो
3	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम
4	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प0 सिंहभूम
5	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला

6	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला - खरसावां
7	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा
8	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लोहरदगा
9	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद
10	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जामताड़ा
11	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग
12	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़
13	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा
14	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू
15	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह
16	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा
17	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार
18	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका
19	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर
20	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा
21	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पाकुड़
22	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी
23	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज
24	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गढ़वा

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उक्त शक्ति अधिसूचित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के लिए लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के उप सचिव ।

अधिसूचना

5 अगस्त, 2014

संख्या-2/रा0. स्था0-36/14-3168/रा.-- श्री संदीप कुमार दोरायबुरु, अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को उनके विभागीय कार्यों के अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act.-2013") की धारा 3(g) के तहत जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार-ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के उप सचिव ।

अधिसूचना

5 अगस्त, 2014

संख्या-2/राज.स्था.-18/10-3144/रा०—संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, (SPT Act)-1949 4 (vii) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 29, 30, 32, 33, 56, 57, 58, 59, 60-2 (ए) तथा 62 के अन्तर्गत **श्री भगवान झा**, अपर समाहर्ता, देवघर को देवघर जिलान्तर्गत राजस्व संबंधी न्यायालय कार्यों के निष्पादन हेतु अपर उपायुक्त, देवघर शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के उप सचिव ।

अधिसूचना

5 अगस्त, 2014

संख्या-2/राज.स्था.-18/10-3147/रा०—छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 तथा 71(ए) के अंतर्गत **श्री मंजूनाथ भजंत्री**, अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल को न्यायालय में लंबित राजस्ववादों के निष्पादन हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त करते हैं।

उक्त पदाधिकारियों को उनके पद से स्थानांतरण अथवा संबन्धित जिलान्तर्गत पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण (जो भी पहले हो) के उपरांत संबंधित अधिसूचना स्वतः विलोपित समझा जायगा।

संख्या-2/राज.स्था.-18/10-3147/रा०—छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 तथा 71(ए) के अंतर्गत **श्री चंद्रभूषण सिंह**, अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला को न्यायालय में लंबित राजस्ववादों के निष्पादन हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त करते हैं।

उक्त पदाधिकारियों को उनके पद से स्थानांतरण अथवा संबन्धित जिलान्तर्गत पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण (जो भी पहले हो) के उपरांत संबंधित अधिसूचना स्वतः विलोपित समझा जायगा।

संख्या-2/राज.स्था.-18/10-3147/रा०-- श्री ईकबाल आलम अंसारी, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था), राँची को राजस्व संबंधी कार्य के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता, राँची की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

उक्त पदाधिकारियों को उनके पद से स्थानांतरण अथवा संबन्धित जिलान्तर्गत पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण (जो भी पहले हो) के उपरांत संबंधित अधिसूचना स्वतः विलोपित समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के उप सचिव ।

अधिसूचना

4 अगस्त, 2014

संख्या-2/राज.स्था.-40/09-3139/रा०-- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46, 47 तथा 71(ए) के अंतर्गत श्री **सुरेन्द्र कुमार वर्मा**, अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर, पलामू को न्यायालय में लंबित राजस्ववादों के निष्पादन हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करते हैं।

उक्त पदाधिकारी के उनके पद से स्थानांतरण अथवा संबन्धित अनुमंडल में नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण (जो भी पहले हो) के उपरांत संबंधित अधिसूचना स्वतः विलोपित समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के उप सचिव ।

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

26 मई, 2014

संख्या- न0प्र0नि0/ NULM -13/2014-2061-- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No. K-14011/1/2013-UPA दिनांक 24 सितम्बर, 2013 तथा D.O. No.-K-14011/1/2013-UPA दिनांक 6 फरवरी, 2014 के आलोक में शहरी गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा का निवारण के लिए पूर्व से संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है। इसके अतिरिक्त यह मिशन शहरी पथ विक्रेताओं/फेरिवालों को उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका संबंधी समस्याओं का निराकरण करना है।

2. उक्त के आलोक में योजना दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर दो स्तरीय समिति एवं निकाय स्तर पर एक समिति गठित किया जाना प्रस्तावित है। नीतिगत निर्णय लेने हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में Governing Council (GC), योजना कार्यान्वयन के निमित्त प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Executive Committee (EC) एवं निकाय स्तर पर NULM के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में Executive Committee (EC) गठित किया जाना है।

3. सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत निम्नलिखित एवं प्रशासनिक निर्णय साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु समितियाँ गठित की जाती हैं, जिनका स्वरूप निम्नानुसार है:-

(i) योजना के दिशा निर्देश के अनुसार योजना के विभिन्न घटकों में नितिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में Governing Council (GC) का गठन निम्न रूप से किया जाता है:-

Sl No.	Designation	Membership
1	Chief Minister	Chairperson
2	Finance Minister	Vice-Chair
3	Minister, Urban Development	Member
4	Minister, Rural Development	Member
5	Minister, Labour & Employment	Member
6	Minister, Industry	Member
7	Minister, Health	Member
8	Minister, Technical Education	Member
9	Chief Secretary	Member
10	State Lead Bank officer	Member
11	Representative of Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, GoI	Member
12-13	Representatives of Urban Local Bodies – Mayors/Chairpersons (2)	Member
14-16	Livelihood Experts/Civil Society/Industry Representatives (3)	Member
17	Secretary/Principal Secretary in charge of NULM	Member-Convenor
18	Any other member's co-opted by the Chairperson	Member

(ii) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में योजना के प्रशासनिक विषयों पर निर्णय हेतु Executive Committee (EC) का गठन निम्न रूप से किया जाता है:-

Sl No.	Designation	Membership
1	Chief Secretary	Chairperson
2	Secretary/Principal Secretary, Urban Development	Member
3	Secretary, Finance	Member
4	Secretary, Rural Development	Member
5	Secretary, Labour & Employment	Member
6	Secretary, Social Welfare	Member
7	Secretary, Health & Family Welfare	Member
8	Secretary, Public Works Department	Member
9	Secretary, Food & Civil Supplies	Member
10	Secretary in charge of Primary Education	Member
11	State Lead Bank officer and Head of another Nationalised Bank	Member
12	State Representative of RBI	Member
13	Industry Representative	Member
14	Representatives of SHGs/Federations (3)	Member
15	State Mission Director, NRLM	Member
16	State officer in charge of Technical Education /k- Labour/Industry	Member
17	Representative of Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	Member
18	State Mission Director, NULM	Member
19	Any other member(s) co-opted by the Chairperson	Member-Convenor

(iii) इसी प्रकार निकाय स्तर पर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में NULM योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु Executive Committee (EC) का गठन निम्न रूप से किया जाता है:-

Sl No.	Designation	Membership
1	Municipal Commissioner	Chairperson
2	officer in charge of NRLM	Member
3	officer in charge of Industry	Member
4	officer in charge of Modular Employable Skills	Member
5	Chief Medical officer	Member
6	District Social Welfare officer	Member
7	Senior-most CE /SE / EE of PWD posted at the district	Member
8	Senior-most district-level officer responsible for primary /k-secondary education	Member
9	District Supply officer	Member
10-11	Representatives of Banks (2)	Member
12-13	Representatives of SHGs/Federations (2)	Member
14	City Project officer, NULM /CEO/EO / Special officer	Member-Convenor
15	Any other member (s) co-opted by the Chairperson Member4.	

प्रस्ताव में मुख्य सचिव, मंत्री नगर विकास विभाग एवं मुख्य मंत्री झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।
